+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

YOJANA MAGAZINE ANALYSIS

(योजना पत्रिका विश्लेषण)

(केंद्रीय बजट - 2025-26)

(March 2025)

(Part I)

TOPICS TO BE COVERED

- उज्जवल भविष्य के लिए बजट निर्धारण
- 'विकसित भारत' 2047 का रोडमैप
- निवेश: विकास का वाहक

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

उज्जवल भविष्य के लिए बजट निर्धारण:

बजट 2025-26: आर्थिक विकास का वाहक

- भारतीय अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में निरंतर प्रगति कर रही है, वैश्विक रुझानों को लगातार चुनौती दे रही है और वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण देश के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत बना रही है।

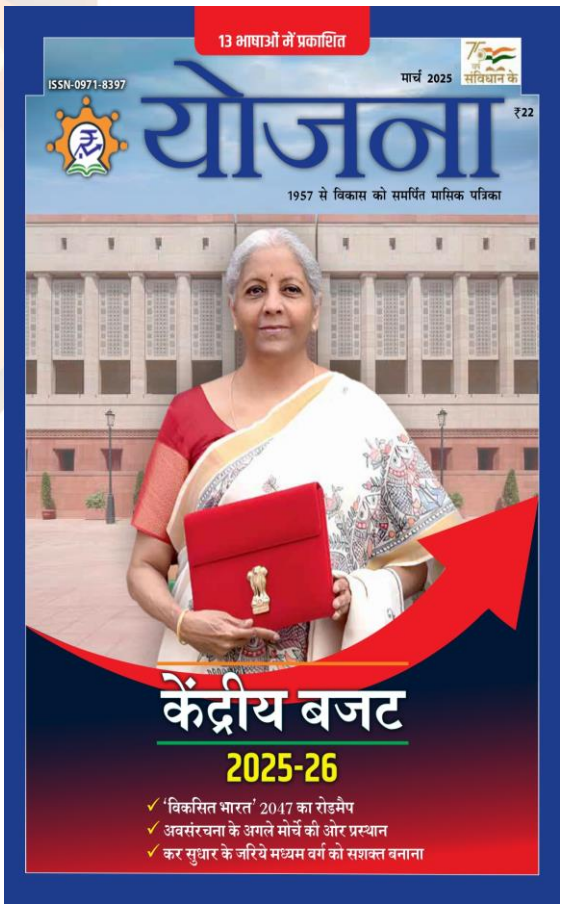

- इस विकास यात्रा की गति को कायम रखते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 ने एक स्पष्ट संकेत दिया है कि सरकार इस गति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें विकास को बढ़ावा देने, निवेश बढ़ाने और अपने नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- बजट में विकास के चार इंजनों का उल्लेख किया गया है अर्थात् कृषि, MSME, निवेश और निर्यात जिनसे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की अपेक्षा है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

बजट में खपत बढ़ाने की पहल:

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा का हाल ही में रेपो दर में कटौती करके इसे 6.25 प्रतिशत तक घटाना मौद्रिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। इस दर में कटौती से प्रणाली में नई तरलता आने की उम्मीद है।
- यह मौद्रिक नीति निर्णय और 12 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट देने के सरकार का कदम प्रभावपूर्ण संयोजन है जिसमें मांग को बढ़ाकर विकास को बढ़ावा देने की संभावना है।
- इसके अलावा इस कदम से मध्यम वर्ग को जो आर्थिक चक्र में एक महत्वपूर्ण कड़ी है बड़ी राहत और खुशी मिली है क्योंकि इससे उनकी डिस्पोजेबल (व्यक्तिगत) आय बढ़ेगी और उन्हें अधिक वित्तीय लचीलापन मिलेगा जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की योजना बना सकेंगे।

कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल:

- भारत सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है और इस क्षेत्र को नवीनतम बजट आवंटन इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कृषि अवसंरचना कोष ने कटाई के बाद के प्रबंधन में सुधार के लिए 87,500 से अधिक परियोजनाओं के लिए 52,738 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

- बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से इस अत्यधिक पौष्टिक फसल की खेती और विपणन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त असम में 12.7 लाख टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र आयातित यूरिया पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद करेगा।

समुद्री बुनियादी ढांचा विकास पर बल:

- केंद्रीय बजट 2025-26 ने एक समर्पित समुद्री विकास कोष की स्थापना के साथ भारत के समुद्री विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की है। जैसा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है यह कोष उद्योग के लिए एक गेम चेंजर होगा जो जहाज निर्माण और अन्य समुद्री बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किफायती और नियमित पूंजी तक पहुंच प्रदान करेगा।

वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों से सतर्क रहने की जरूरत:

- इस जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ते हुए हमें उन प्रतिकूल परिस्थितियों से भी सतर्क रहना चाहिए जिनका सामना दुनिया कर रही है। युद्धों ने तेल की आपूर्ति और व्यापार मार्गों को बाधित किया है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इस परिदृश्य में भारत को इन चुनौतियों का सावधानीपूर्वक सामना करना होगा ताकि विकास का लाभ निर्धनतम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

'विकसित भारत' 2047 का रोडमैप:

परिचय:

- 1991 के आर्थिक सुधारों ने वैश्वीकरण का लाभ उठाकर भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की नींव दी। भुगतान संतुलन संकट और आर्थिक स्थिरता की चुनौतियों के बीच, भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई।
- 1991 के सुधारों ने भारत की आर्थिक नीति में बड़ा बदलाव लाया, संरक्षणवादी नीतियों को हटाकर देश को विदेशी निवेश, व्यापार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खोला। इस त्वरित बदलाव ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने, आर्थिक विकास बढ़ाने, रोजगार सृजन करने और औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों के विस्तार में मदद की।

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की विकास यात्रा: चुनौतियां और अवसर

- भारत के आर्थिक बुनियादी ढांचे की मजबूती बदलती वैश्विक व्यवस्था और अनुकूल नीतियों का परिणाम रही है। लेकिन अब, लगभग 30 साल बाद, वैश्वीकरण के दौर

के अंत, संरक्षणवाद के उदय, व्यापार गतिशीलता में बदलाव और भू-राजनीतिक तनावों के कारण नई चुनौतियां उभर रही हैं। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब घरेलू आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखलाओं में पुनर्गठन हो रहा है। ये बदलाव महामारी से प्रेरित झटकों के लिए केवल एक अस्थायी प्रतिक्रिया नहीं हैं, बल्कि वैश्विक आर्थिक विकास के तरीकों में एक संरचनात्मक परिवर्तन का संकेत देते हैं, जिससे भारत को अपनी विकास रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

- 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में उच्च विकास बनाए रखना एक चुनौती होगी, क्योंकि पारंपरिक विकास मॉडल अब उतने प्रभावी नहीं हो सकते। भू-आर्थिक विखंडन, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन भारत की उत्पादन और ऊर्जा नीतियों को प्रभावित करेंगे। साथ ही, 2036 तक हर साल 78.5 लाख गैर-कृषि नौकरियों का सृजन, 100% साक्षरता, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और तेज़ी से बुनियादी ढांचे का विकास आवश्यक होगा। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना और आंतरिक विकास वाहकों को पुनः सक्रिय करना होगा।

आत्मनिर्भर भारत: आंतरिक विकास वाहकों के माध्यम से समृद्धि

- उल्लेखनीय है कि बिना किसी अनुकूल बाहरी स्थितियों के आंतरिक विकास वाहकों पर निर्भर रहना, हमारे विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की कुंजी रही है।
- इस प्रकार घरेलू वाहकों को उत्प्रेरित करना चार मुख्य प्राथमिकताओं को पूरा करने पर निर्भर करता है: व्यापक विनियमन सुधार, मजबूत विनिर्माण आधार, भारत-केंद्रित ऊर्जा परिवर्तन एवं ऊर्जा सुरक्षा और सरकार, निजी क्षेत्र व शिक्षाविदों के बीच सहयोग। बदलते वैश्विक परिदृश्य में, भारत की विकास क्षमता इस पर निर्भर करेगी कि वह अपनी आर्थिक रणनीतियों को कितनी प्रभावी तरीके से पुनर्गठित करता है।
- साहसिक सुधारों और घरेलू परिवर्तनशीलता को बढ़ावा देकर, भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकता है और नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार जारी रख सकता है।

विकास के लिए व्यापक विनियमन सुधार:

- 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत में लाइसेंस राज को समाप्त करके उद्यमशीलता और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, जिससे व्यापार-अनुकूल माहौल बना और आर्थिक विकास तेज हुआ। हालांकि, यह एक सतत प्रक्रिया रही है, जिसमें भारत

सरकार ने पिछले एक दशक में शासन और विनियमन सुधारों को प्राथमिकता दी है। इन नीतिगत प्रयासों का उद्देश्य विनियमन को सरल बनाना और आर्थिक गतिविधियों को अधिक सुगम बनाना है।

विनियमन सुधार और आर्थिक परिवर्तन (2014 से वर्तमान):

- 2014 से, सरकार ने व्यापार-अनुकूल माहौल बनाने के लिए 20,000 से अधिक अनुपालनों को सरल बनाया, 300 कानूनों में दंड को हटाया/सरल किया, और प्रमुख क्षेत्रों को विशेष लाभ प्रदान किए।
- प्रमुख सुधारों में कर और श्रम कानूनों का सरलीकरण, व्यवसाय से जुड़े नियमों का अपराधमुक्तकरण, और वन विनियमों में संशोधन शामिल हैं ताकि बुनियादी व्यावसायिक गतिविधियों में बाधाएं कम हों।
- संरचनात्मक सुधारों में जीएसटी, आईबीसी, और रेरा लागू किए गए, जिससे कर प्रणाली सरल हुई, दिवाला समाधान सुगम बना और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ी। इंडिया स्टैक (यूआईडी, यूपीआई, डीबीटी) के जरिए प्रशासनिक दक्षता बढ़ी और लीकेज कम हुए।
- ये सुधार राज्यों के लिए अगली पीढ़ी के आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिससे समग्र विकास को गति मिलेगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

अत्यधिक विनियमन विकास का बाधक:

- विनियमन आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जिससे व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनता है, निवेश प्रवाहित होता है और रोजगार सृजन को गति मिलती है। लेकिन अत्यधिक विनियमन छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) पर भारी लागत डालता है, जिससे वे जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जूझते हैं।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, SMEs भवन मानकों के कारण अपनी जमीन का 50% तक खो सकते हैं, और कड़े श्रम नियम उन्हें बढ़ती मांग के अनुसार उत्पादन बढ़ाने से रोकते हैं।
- इसके अलावा, यूजीसी और एआईसीटीई के कड़े नियम उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम को लचीले ढंग से बदलने और बाजार की जरूरतों के अनुसार शिक्षा को अनुकूलित करने से रोकते हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी के विकास में बाधा आती है।
- एक सुव्यवस्थित विनियमन-मुक्ति रणनीति प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ाती है, निजी निवेश को आकर्षित करती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को कम करती है।

साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग हो, जिससे व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बने और वे बाजार की मांगों व तकनीकी प्रगति के अनुसार प्रतिक्रिया दे सके।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वे राज्य जहां व्यापार करना आसान है, वहां औद्योगिक गतिविधि अधिक देखी गई है। यह अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से मेल खाता है, जिससे उपभोक्ता कल्याण, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है।

बजट में विनियमन सुधारों के माध्यम से विकास पर बल:

- हालिया बजट सुधारों से सरकार की विनियमन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। इसमें आयकर अधिनियम को सरल बनाना, द्विपक्षीय निवेश संधियों को निवेशक-अनुकूल बनाना और व्यापार व जीवन सुगमता में सुधार शामिल है।
- इसके अलावा, गैर-वित्तीय क्षेत्रों के विनियमन की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो व्यापारिक माहौल को बदलने और नए विकास अवसरों को खोलने में मदद करेगी।

- उल्लेखनीय है कि एक ऐसे युग में जहां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बदल रही हैं और अर्थव्यवस्थाएं अपनी निर्भरता का पुनर्मूल्यांकन कर रही है, लचीला और कुशल नियामक ढांचा रखने वाले देश अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में आगे रहेंगे। ऐसे में उचित विनियमन से आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है, घरेलू उद्योग मजबूत होते हैं, और वैश्विक निवेश आकर्षित होता है, जिससे सतत और समावेशी विकास संभव होता है।

बल गुणक के रूप में मजबूत विनिर्माण आधार:

विनिर्माण शक्ति और आर्थिक सक्षमता:

- इतिहास में, विनिर्माण शक्ति किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का प्रतीक रही है। प्राचीन भारतीय साम्राज्य (चोल, गुप्त), मध्ययुगीन यूरोप, 19वीं सदी का ब्रिटेन, और 20वीं सदी का अमेरिका इसके उदाहरण हैं।
- पूर्वी एशिया ने 1970 के दशक में विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से लाखों लोगों को गरीबी से निकाला, जीवन स्तर सुधारा और युवाओं को कुशल कार्यबल में बदला। चीन, जो वर्ष 2000 में वैश्विक विनिर्माण में 6% हिस्सेदारी रखता था, अब 2030 तक 45% हिस्सेदारी तक पहुँचने की उम्मीद रखता है। इससे वह अमेरिका और उसके सहयोगियों को चुनौती दे सकता है।

विनिर्माण: एक आर्थिक बल गुणक

- विनिर्माण को तीन प्रमुख पहलुओं के कारण एक बल गुणक माना जाता है:

1. **औद्योगिक नेटवर्क निर्माण:** यह ऊर्ध्वाधर (self-sustained ecosystems) जैसे वियतनाम की फाइबर-टू-फैशन कंपनियों या कोरिया की पोत निर्माण कंपनियों और क्षैतिज (interconnected industries) नेटवर्क के रूप में विकसित हो सकता है, जैसे चीन का औद्योगिक विस्तार।
2. **कौशल विकास:** यह फर्म-स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देता है, जिससे कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं को बिना भारी शिक्षा निवेश के भी लाभ मिलता है, जैसा कि पूर्वी एशिया में देखा गया।
3. **अवसंरचना और शासन सुधार:** एक सशक्त विनिर्माण क्षेत्र बुनियादी ढांचे के विकास, शासन सुधार, और विनियामक बाधाओं को कम करने में मदद करता है, जैसा कि 19वीं सदी के इंग्लैंड में हुआ। हानाँडो डी सोटो ने अपनी पुस्तक 'द मिस्ट्री ऑफ कैपिटल' में बताया कि औद्योगिक क्रांति से पहले, इंग्लैंड ने अपने संस्थानों और शासन में सुधार किया था, जिससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत में विनिर्माण का विस्तार और प्रौद्योगिकी उन्नति:

- भारत को 2030 तक हर साल 80 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करना आवश्यक है।
- विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देने वाली प्रमुख पहले:

1. ऋण सहायता:

➢ एमएसई और टीआरईडीएस के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत ₹1.38 लाख करोड़ का वित्तपोषण (FY 2024)।

➢ म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना – ₹100 करोड़ तक की मशीनरी खरीदने वाले एमएसएमई को 60% ऋण गारंटी।

2. बुनियादी ढांचा सुधार:

➢ 2014-2024 के बीच बंदरगाहों पर प्रत्यावर्तन समय आधा हुआ।

➢ भारत का विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक रैंक 54 से 38 पर पहुंचा।

3. प्रौद्योगिकी और उद्योग 4.0:

➢ एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, सेमीकंडक्टर्स, जैव प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा में उन्नति आवश्यक।

➢ पीएलआई (Production-Linked Incentive) योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन: एयर कंडीशनर उद्योग में आत्मनिर्भरता; दूरसंचार में 60% आयात प्रतिस्थापन; और सौर फोटोवोल्टिक, बैटरी भंडारण और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को बढ़ावा।

श्रम-गहन और प्रौद्योगिकी-गहन उद्योगों के बीच संतुलन की जरूरत:

- भारत को औद्योगिक विकास के लिए श्रम-गहन और प्रौद्योगिकी-गहन उद्योगों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है।
- युवा जनसंख्या को देखते हुए, रोजगार और सामाजिक स्थिरता के लिए श्रम-गहन विकास आवश्यक है, लेकिन प्रौद्योगिकी-गहन उद्योगों की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये उद्योग श्रम-गहन क्षेत्रों के पूरक बन सकते हैं, जिससे नौकरियां समाप्त किए बिना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता बढ़ेगी।
- इस रणनीति से संरचित विनियमन के तहत एक मजबूत एसएमई (मित्तलस्टैंड) क्षेत्र विकसित होगा, जिससे समावेशी औद्योगिक विकास संभव होगा।

भारत-केंद्रित ऊर्जा परिवर्तन एवं ऊर्जा सुरक्षा:

- भारत के आर्थिक विकास में जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका है। पश्चिमी देशों ने बिना विश्वसनीय नवीकरणीय विकल्पों के

जीवाश्म ईंधन से हटने की जल्दबाजी में ऊर्जा संकट और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा में गिरावट झेली है। भारत को इन गलतियों से बचते हुए ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता देनी चाहिए।

- भारत का ऊर्जा परिवर्तन व्यावहारिक और चरणबद्ध होना चाहिए, जहां अक्षय ऊर्जा का विस्तार हो, लेकिन पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को समय से पहले बंद करने की कीमत पर नहीं। भारत की रणनीति चरणबद्ध और तकनीकी रूप से समावेशी होनी चाहिए—नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार किया जाए, लेकिन पारंपरिक ऊर्जा को जल्दबाजी में खत्म न किया जाए।
- उल्लेखनीय है कि परमाणु ऊर्जा में निजी भागीदारी और तकनीकी सहयोग से 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ऊर्जा दक्षता और मांग प्रबंधन के लिए लाइफ आंदोलन और सार्वजनिक परिवहन का विस्तार जैसे कदम आवश्यक हैं।
- संधारणीयता और सामर्थ्य के संतुलन के साथ, भारत ऐसी नीतियां अपना सकता है जो औद्योगिक विकास को बाधित करने के बजाय उसे गति दें और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करें।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

समृद्ध भारत के लिए त्रिपक्षीय सहमति:

- औद्योगिक परिवर्तन में सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जैसा कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया था। पूंजी और श्रम के निष्पक्ष वितरण से दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और लाभप्रदता सुनिश्चित होती है। उल्लेखनीय है कि पीटर टेमिन के शोध के अनुसार, ऐतिहासिक रूप से श्रमिकों की कमी ने तकनीकी नवाचार और पूंजी-आधारित विकास को बढ़ावा दिया, लेकिन श्रम-समृद्ध समाजों को संतुलित रणनीति अपनाने की आवश्यकता है।
- तकनीकी प्रगति जैसे एआई, आईओटी और 3डी प्रिंटिंग भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बना रहे हैं, लेकिन स्वचालन से कम-कुशल श्रमिकों की मांग घट सकती है। इसलिए, कार्यबल को फिर से प्रशिक्षित करने और रोजगार पर प्रभाव को संतुलित करने की आवश्यकता है।
- भारत को सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र के बीच सहयोग से एक संतुलित नीति अपनानी चाहिए, जिससे तकनीकी विकास और रोजगार सृजन दोनों को बढ़ावा मिले।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- निजी क्षेत्र को कौशल विकास में निवेश, समावेशी स्वचालन रणनीतियां अपनाने और ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण का विस्तार करने पर ध्यान देना चाहिए।
- शिक्षा और अनुसंधान को उद्योग की जरूरतों से जोड़ना आवश्यक है। स्टैम शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण से श्रम-गहन व तकनीकी-गहन दोनों उद्योगों को लाभ मिलेगा। उद्यमिता और नवाचार केंद्रों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।

निष्कर्ष:

- उल्लेखनीय है कि भारत की 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा सिर्फ एक आकांक्षा नहीं, बल्कि आर्थिक, जनसांख्यिकीय और भू-राजनीतिक आवश्यकता है। आर्थिक विखंडन के युग में उच्च विकास बनाए रखने के लिए आंतरिक विकास स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिसमें विनियामक सुधार, विनिर्माण क्षेत्र का पुनरुद्धार, ऊर्जा सुरक्षा और सरकार-निजी क्षेत्र-शिक्षाविदों के बीच तालमेल शामिल हैं।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- वर्तमान में भारत एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है, जहां नीतिगत फैसले यह तय करेंगे कि वह उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनेगा या मध्यम आय के जाल में फंसेगा। इस परिवर्तन के लिए स्थिर आर्थिक नीतियां, कुशल शासन और नवाचार-संचालित निजी क्षेत्र आवश्यक हैं। इतिहास बताता है कि जो राष्ट्र बदलाव के अनुरूप खुद को ढालते हैं, वे आगे बढ़ते हैं, जबकि जो देरी करते हैं, वे पिछड़ जाते हैं। भारत की अनुकूलन क्षमता अगले दो दशकों के विकास पथ को परिभाषित करेगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

निवेश: विकास का वाहक

परिचय:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में 'कृषि, MSME, निवेश और निर्यात' को विकास यात्रा के शक्तिशाली इंजनों के रूप में महत्व दिया गया है। इसमें 'सुधार' ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, 'समावेशिता' मार्गदर्शक सिद्धांत है, और 'विकसित भारत' गंतव्य है।
- चार-इंजन विकास मॉडल को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करे, ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा दे, MSME को सशक्त बनाए, मानव संसाधन, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करे, निर्यात को बढ़ावा दे, और भारतीय नागरिकों के समग्र कल्याण को समावेशी दृष्टिकोण के साथ सुनिश्चित करे।

- इस बजट का विकास एजेंडा 'ज्ञान फ्रेमवर्क' (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी) पर केंद्रित है, जो भारत के समावेशी, समग्र और सतत विकास को प्रोत्साहित करता है।

विकास का तीसरा इंजन: निवेश

- बजट 2025-26 में 'विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश' को विशेष महत्व दिया गया है, जो मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है- लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश।
- लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश न केवल आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, बल्कि भारत की सामाजिक-आर्थिक विकास गाथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए भी आवश्यक है।

लोगों में निवेश (Investing in People):

- **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0:** सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है।
- **अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं:** बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में पचास हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम:** स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है।
- **राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र:** जुलाई, 2024 के बजट में घोषित की गई पहलों की दिशा में कार्य करते हुए, वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा ताकि "मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके।
- **IIT में क्षमता का विस्तार:** विगत 10 वर्षों में 23 IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा ताकि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके।
- **शिक्षा के लिए 'एआई में उत्कृष्टता केंद्र':** 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धारणीय शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी तीन उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की गयी थी।

अब 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा।

- **चिकित्सा शिक्षा का विस्तार:** भारत सरकार ने पिछले दस वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130 प्रतिशत की वृद्धि है। साथ ही अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
- **सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र:** भारत सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- **पीएम स्वनिधि (SVANidhi) योजना को नया रूप:** पीएम स्वनिधि योजना से अब तक 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ मिला है, जिससे उन्हें ऊंची ब्याज दर वाले अनौपचारिक ऋणों से राहत मिली। इसकी सफलता को देखते हुए, योजना को बैंकों से बढ़े हुए ऋण, ₹30,000 की सीमा वाले यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड, और क्षमता निर्माण सहायता के साथ नया रूप दिया जाएगा।
- **'गिग कामगारों' के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना:** गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण और

पहचान पत्र जारी करने की व्यवस्था करेगी। साथ ही, उन्हें PM जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल सुविधा मिलेगी, जिससे लगभग 1 करोड़ कामगारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

अर्थव्यवस्था में निवेश (Investing in Economy):

- **बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निजी भागीदारी:** बुनियादी ढांचे से संबंधित प्रत्येक मंत्रालय 3 साल की परियोजनाओं की पाइपलाइन लेकर आएगा, जिन्हें PPP मोड में लागू किया जा सकता है। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे PPP प्रस्ताव तैयार करने के लिए IIPDF (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड) योजना से सहायता मांग सकते हैं।
- **बुनियादी ढांचे के लिए राज्यों को सहायता:** पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।
- **परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30:** वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए, नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपये की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा।

- **2028 तक जल जीवन मिशन योजना का विस्तार:** वर्ष 2019 से अब तक 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है जो ग्रामीण आबादी का 80 प्रतिशत हिस्सा है। इस वर्ष के बजट में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए, बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ इस मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा की गयी है।
- **'शहरी चुनौती निधि' की स्थापना:** सरकार 'शहरों को विकास केंद्र', 'शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास' और 'जल एवं स्वच्छता' को लागू करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की 'शहरी चुनौती निधि' स्थापित करेगी। यह निधि बैंक योग्य परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्तपोषित करेगी, बशर्ते कि 50% वित्तपोषण बांड, बैंक ऋण या PPP से हो। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है।
- **विकसित भारत के लिए 'परमाणु ऊर्जा मिशन':** 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और सिविल दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन किए जाएंगे, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी संभव होगी। 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'परमाणु ऊर्जा मिशन' स्थापित किया जाएगा, जो लघु मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) के अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR क्रियाशील होंगे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **समुद्री विकास निधि स्थापना:** समुद्री उद्योग के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण के लिए 25,000 करोड़ रुपये की राशि वाला 'समुद्री विकास निधि' स्थापित किया जाएगा। यह वितरित या भागीदारी समर्थन और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए होगा। इसमें सरकार का 49 प्रतिशत तक योगदान होगा और शेष राशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी।
- **संशोधित 'उड़ान' स्कीम:** उड़ान योजना ने 1.5 करोड़ मध्यमवर्गीय यात्रियों की यात्रा आकांक्षाओं को पूरा करते हुए 88 हवाई अड्डों और 619 मार्गों को जोड़ा है। इसकी सफलता के आधार पर, एक संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी, जिससे अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाया जाएगा और 4 करोड़ यात्रियों को लाभ मिलेगा।
- **SWAMIH फंड 2.0:** SWAMIH योजना के तहत अब तक 50,000 संकटग्रस्त आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर घर खरीदारों को सौंपा गया है, जबकि 2025 में 40,000 और इकाइयाँ पूरी होंगी। इसकी सफलता को देखते हुए, सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के सहयोग से 15,000 करोड़ रुपये का SWAMIH फंड 2.0 स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 1 लाख अतिरिक्त आवासीय इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है।

- **रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन:** देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड में विकसित किया जाएगा। पर्यटन में रोजगार उन्मुख विकास के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे:
  - ➢ युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रम, आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों को शामिल करते हुए।
  - ➢ होमस्टे के लिए मुद्रा ऋण की सुविधा।
  - ➢ पर्यटन स्थलों की यात्रा और संपर्क में सुधार।
  - ➢ पर्यटकों की सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन बेहतर करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन सहायता।
  - ➢ कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीजा-शुल्क छूट और ई-वीजा सुविधा।
- इसके अलावा, आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

नवाचार में निवेश (Investing in Innovation):

- **अनुसंधान, विकास और नवाचार:** जुलाई 2024 के बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए, 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- **डीप टेक 'फंड ऑफ फंड्स':** इस पहल के एक भाग के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की भी संभावना तलाशी जाएगी।
- **पीएम रिसर्च फेलोशिप:** अगले पांच वर्षों में, 'पीएम रिसर्च फेलोशिप' योजना के तहत, बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISC में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान किया जायेगा।
- **फसल जर्मप्लाज्म के लिए जीन बैंक:** भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को आनुवंशिकी अनुसंधान के लिए संरक्षण सहायता प्रदान करेगी।
- **राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन:** भारत सरकार आधारभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए एक 'राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन' शुरू करेगी। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए, यह मिशन भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के डिजाइन की सुविधा प्रदान करेगा।

- **ज्ञान भारतम मिशन:** शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए 'ज्ञान भारतम मिशन' शुरू किया जाएगा जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा।

'भविष्य के भारत-2047' के लिए मार्ग और रूपरेखा:

- केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस 'विकसित भारत-2047' के दृष्टिकोण पर है, जो अर्थव्यवस्था के समावेशी, सतत और एकीकृत विकास को बढ़ावा देता है। इसमें कृषि, MSME, निवेश और निर्यात संवर्धन को प्राथमिकता दी गई है।
- यह लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किफायती स्वास्थ्य सेवाएं, और महिलाओं, श्रमिकों व किसानों की सक्रिय भागीदारी से ही संभव होगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांतों और संरचनात्मक सुधारों से बल मिल रहा है।
- उल्लेखनीय है कि सच्चा विकास तभी संभव है, जब सभी क्षेत्रों का संतुलित और समावेशी विकास हो और इसके लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें। नागरिकों के सशक्तिकरण और समृद्धि से ही भारत वैश्विक नेतृत्व स्थापित कर सकेगा।